

बिहार विशिष्ट करेंट अफेयर्स: जुलाई 2021

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व CAITS मान्यता प्राप्त करने वाले 14 टाइगर रिजर्व में से एक बन गया।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने घोषणा की है कि भारत के 14 टाइगर रिजर्व्स को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स (CAITS) से मान्यता प्राप्त हुई है।
- टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं: असम (3), मध्य प्रदेश (2), तमिलनाडु (2), महाराष्ट्र (1), बिहार (1), उत्तर प्रदेश (1), पश्चिम बंगाल (1), केरल (1), कर्नाटक (1)।
- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, टाइगर रिजर्व में से एक है जिसे मान्यता प्राप्त हुई है।
- घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 को की गई थी, जिसे 29 जुलाई 2021 को मनाया गया था।
- टाइगर रिजर्व की घोषणा के साथ, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट "तेंदुओं, सह-शिकारियों और पूर्ण शाकाहरियों की 2018 की स्थिति" और "STRIPES" का विशेष संस्करण भी जारी किया, जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का त्रैमासिक समाचार पत्र है।
- संबंधित समाचारों में, असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 200 हो गई है। 2021 में, काजीरंगा में 121 बाघ, मानस में 48, ओरंग में 28 और नामेरी टाइगर रिजर्व में 3 बाघ हैं।

पटना उन 10 शहरों में शामिल है जहाँ सामाजिक न्याय और पर्यावरण मंत्रालय की SMILE योजना लागू की जाएगी

- सामाजिक न्याय और पर्यावरण मंत्रालय ने देश में भिखारियों के कल्याण के लिए एक योजना की घोषणा की है। SMILE- देश में लाखों भिखारियों को सहायता और कल्याण प्रदान करने के लिए आजीविका और उद्यम योजना के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता शुरू की गई है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य पुनर्वास, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, चिकित्सा आवश्यकता, पहचान, शिक्षा आदि होगा।
- यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, संस्थानों और अन्य को अपने साथ शामिल करेगी।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए मौजूदा आश्रय गृहों का उपयोग भिखारियों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा, उन क्षेत्रों में जहाँ कोई मौजूदा आश्रय गृह उपलब्ध नहीं है, संबंधित एजेंसियां भिखारियों के पुनर्वास के लिए नए आश्रय गृह विकसित करेंगी।
- पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना निम्नलिखित 10 शहरों में लागू की जा रही है: दिल्ली, बेंगलोर (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), इंदौर (मध्य प्रदेश), लखनऊ (यूपी), मुंबई (महाराष्ट्र), नागपुर (महाराष्ट्र), पटना (बिहार) और अहमदाबाद (गुजरात)।

बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच पहला ट्रेन परिचालन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया

- 18 जुलाई 2021 को, भारत और नेपाल के बीच पहली हाई स्पीड रेल लाइन का बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर और नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था के बीच सफल परीक्षण किया गया।
- 50 km लंबी रेलवे लाइन परियोजना 619 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है और मार्ग के साथ 5 रेलवे स्टेशनों (जयनगर, इनरवा, खजूरी, बैदेही और कुर्था) को कवर करती है।
- रेलवे लाइन का निर्माण भारत-नेपाल मैत्री परियोजना के तहत IRCON (इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड) द्वारा किया गया है। इस परियोजना को भारत संघ द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
- हाई-स्पीड ट्रेन 115 km प्रति घंटे की रफ्तार से 50 km की दूरी 23 मिनट में तय करेगी। 34 km लंबी रेल लाइन का निर्माण अभी बाकी है; इसे दो चरणों में बनाया जाएगा। पहला चरण नेपाल में कुर्था से भंगहा (17 km) तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और दूसरा चरण भागहा को नेपाल (17 km) में बर्दीबास से जोड़ेगा।
- कौंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL), भारतीय रेलवे के एक हिस्से ने जयनगर-कुर्था रेलवे लाइन परियोजना के लिए नेपाल को दो आधुनिक DEMU (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेनें दी हैं।

बिहार में 2019 के बाद से बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें दर्ज की गईं

तड़ित वातावरण में बिजली का एक बहुत तेज़ और बड़े पैमाने पर निर्वहन है। यह एक प्राकृतिक 'बहुत कम अवधि का विद्युत निर्वहन और एक बादल और जमीन के बीच या एक बादल के भीतर, एक उज्ज्वल फ्लैश और ध्वनि के साथ, और कभी-कभी गरज के साथ उच्च वोल्टता' की घटना की प्रक्रिया है।

- हाल ही में, दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में देश भर में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं।
- अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 401 लोगों की मौत हुई।
- बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है जहाँ 228 मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा और झारखंड में क्रमशः 156 और 132 मौतें हुई हैं।
- बिहार को छोड़कर अधिकतम राज्यों ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों में गिरावट दर्ज की है, जिसमें 2019 से 2020 के बीच मौतों में 80% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलाकर पूरे देश में बिजली गिरने में 34% की वृद्धि हुई है।

बिहार के सांसदों द्वारा लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण के लिए निजी सदस्य विधेयक

- बिहार के औरंगाबाद जिले के सांसद (भाजपा) सुशील कुमार सिंह राष्ट्रीय जनसंख्या योजना समिति और जिला जनसंख्या योजना समिति की स्थापना के उद्देश्य से लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश करने जा रहे हैं।
- JD(U) सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन द्वारा एक और निजी सदस्य विधेयक पेश किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय सुझाना है। बिल 2 बच्चों तक के छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देता है।
- उत्तर प्रदेश और असम की विधानसभा में ऐसे विधेयकों के पेश होने के बाद जनसंख्या नियंत्रण उपाय विधेयक चर्चा का विषय रहा है। एक स्वतंत्र डेटा विश्लेषण के अनुसार, वर्तमान में 540 सांसदों में से 168 के 2 से अधिक बच्चे हैं।